कोई रास्ता निकालना ही होगा

आखिर सामान्य आर्थिक गतिविधियों और यात्राओं पर कब तक पाबंदी लगाए रखी जा सकती है? कोरोना वायरस अगर लंबे समय तक बना रहने वाला है तो दुनिया को उसकी मौजूदगी में सुरक्षित ढंग से जीने का कोई न कोई रास्ता निकालना ही होगा।

रमन सिंह।

अभी न तो कोरोना की दूसरी लहर पूरी तरह काबू में आई है और न संक्रमण से जुड़ी चिंताएं समाप्त हुई हैं, बावजूद इसके यूरोपीय देशों में ग्रीन पास को लेकर विवाद शुरू हो गया है। ईयू देशों ने कोरोना संक्रमण में सुधार के मद्देनजर आवाजाही की व्यवस्था को सामान्य बनाने के मकसद से यह कवायद शुरू की है। पहली नजर में यह तर्कसंगत भी लगती है। आखिर सामान्य आर्थिक गतिविधियों और यात्राओं पर कब तक पाबंदी लगाए रखी जा सकती है? कोरोना वायरस अगर लंबे समय तक बना रहने वाला है तो दुनिया को उसकी मौजूदगी में सुरक्षित ढंग से जीने का कोई न कोई रास्ता निकालना ही होगा। रास्ता निकालने की ऐसी ही एक कोशिश ईयू ने ग्रीन पास जारी करके की है।

हालांकि अभी मामला ईयू देशों के बीच यात्राओं का ही है। इन यात्राओं के लिए भी ग्रीन पास अनिवार्य नहीं है, लेकिन यह यात्रा को आसान और सुविधाजनक जरूर बनाएगा। जिन लोगों के पास ग्रीन पास नहीं होगा उन्हें जगह–जगह आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने और एक निश्चित समय क्वारंटीन में बिताने जैसी असुविधाएं झेलनी पड़ सकती हैं। निकट भविष्य में यूरोप यात्रा की योजना बना रहे भारतीयों के लिए दिक्कत की बात यह रही कि भारत में लगाए जाने वाले तीनों टीकों– कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पूतनिक वी को ईयू की सूची में शामिल नहीं किया गया। इससे जहां भारतीय यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली थी, वहीं भारतीय टीकों की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठ रहा था। जिन टीकों को भारत सरकार ने पूरी जांच–पड़ताल के बाद मान्यता दी हो, उन्हें अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अन्य सरकारें मान्यता देने लायक न मानें तो तकनीकी तौर पर उसकी जो भी वजहें गिनाई जाएं, उसका यह मतलब तो निकलता ही है कि भारतीय संस्थाओं की प्रामाणिकता संदिग्ध है। स्वाभाविक ही, भारत सरकार ने तकनीकी सवालों में उलझने के बजाय इसे सीधे कूटनीतिक स्तर पर उठाया और ईयू और यूरोपीय देशों को साफ तौर पर जतला दिया कि भारत ऐसा दोहरा व्यवहार स्वीकार नहीं करने वाला। जो देश कोविन पोर्टल से सत्यापित प्रमाणपत्र को मान्यता नहीं देंगे, वह उनके प्रमाणपत्र को अमान्य करेगा। भारत के इस कड़े रुख का असर भी देखने को मिला जब आठ ईयू देशों ने कोविशील्ड को मान्यता देने की बात कही। इनमें एस्टोनिया ने तो भारत में मान्य सभी टीकों को मान्यता दी है। इनके अलावा स्विट्जरलैंड ने भी कोविशील्ड को मान्यता दी है। वह ईयू में शामिल नहीं है। हालांकि टीकों की प्रामाणिकता को लेकर आश्वस्त होने की जहां तक बात है तो हर देश और संबंधित एजेंसियों को उसका अधिकार है। वैसे भी फिलहाल ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद हैं। इसलिए इस मामले का कोई तात्कालिक महत्व नहीं है पर यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आगे भी टीका निर्माता कंपनियों की आपसी प्रतिद्वंद्विता या किसी भी अन्य वजह से भारतीय टीकों और भारतीय यात्रियों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए।

पछतावा

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा। वे सोचने लगे, उन्हें बड़ा घमंड था कि उनसे बढ़कर त्रिलोक में दूसरा कोई भक्त नहीं है। लेकिन एक स्त्री को देखकर वे भगवान को भूल गए, उसको पछतावा होने लगा और उनका घमंड जरा–सी देर में ढेर हो गया। वे पुनः सरलता और विनय के साथ भगवान के गुण गाने लगे। एक बार फिर देवर्षि नारद के मन में यह अभिमान पैदा हो गया कि वे ही भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। वे सोचने लगे, मैं रात–दिन भगवान विष्णु का गुणगान करता हूँ। फिर इस संसार में मुझसे बड़ा भक्त और कौन हो सकता है ? किन्तु पता नहीं श्रीहरि मुझे ऐसा समझते हैं या नहीं ? यह विचार कर नारद भगवान विष्णु के पास क्षीर–सागर में पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया। विष्णु जी बोले – आओ नारद, कहो कैसे आना हुआ ?
नारद बोले – भगवन, मैं आपसे एक बात पूछने आया हूँ।

संपादकीय

मान्यता नहीं, मेलजोल

भारत को अपनी नीतियां खुद तय करनी होंगी। तालिबान अगर भारत के पड़ोसी होते हैं तो भारत को उनसे मेलजोल बढ़ाना होगा, लेकिन मेलजोल का मतलब तालिबानों को मान्यता देना नहीं होता। जहां तक मान्यता की बात है तो रूस भी अभी तक मान्यता देने को तैयार नहीं है। इसलिए, जहां तक हो सके, मेलजोल बढ़ाएं। अगर भारत की बात करें तो उसे अब अमेरिका का मुंह ताकने की कोई जरूरत नहीं है। पिछले 20 वर्षों से अमेरिका ने एक चौरिटी के तौर पर भारत को अफगानिस्तान में एक सुरक्षा कवच दे रखा था, जिससे भारत वहां बिजनेस और बाकी समझौते कर पा रहा था। अब अमेरिका बस इतना कर सकता है कि अपनी धमक का इस्तेमाल करे। हम देख ही रहे हैं कि दोनों पक्ष लगातार बात कर रहे हैं। अमेरिका के पास वहां के ढेरों फंड्स हैं, जो उसने रोक रखे हैं और तालिबान चाहता है कि ये फंड जल्द से जल्द रिलीज किए जाएं। लेकिन इसके लिए तालिबान को अमेरिका को कुछ गारंटी देनी होगी। वहां पर हिंदुस्तान की बात रखी जा सकती है कि आप क्या गारंटी देंगे कि भारत को कुछ नहीं होगा? तालिबान कह सकता है कि वह पाकिस्तान के रास्ते व्यापार कर सकता है, लेकिन भारत के पास उस तरफ यानी ईरान में चाबहार बंदरगाह है। भारत कह सकता है कि वह चाबहार की ओर से यह काम शुरू करेगा।

इस तरह दुनिया के इस हिस्से की राजनीति कहीं न कहीं 1996 वाली राजनीति की ओर बढ़ती दिख रही है जो अफगानिस्तान को अस्थिरता और गृहयुद्ध की ओर ले जा सकती है।

बढ़ती मुसीबतें

हर्ष पंत।।

आखिरकार तालिबान नहीं बदला। काबुल की नई सरकार में वे चेहरे हैं, जो 1996 की पिछली तालिबान सरकार की याद दिलाते हैं। तालिबान कह तो रहा था कि वह अफगानिस्तान में सर्वमान्य सरकार बनाएगा, लेकिन जो चेहरे इसमें शामिल किए गए हैं, उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। वहीं, अफगानिस्तान में पाकिस्तानी दखल के कारण न सिर्फ वहां के नागरिक नाराज हैं, सड़कों पर हैं बल्कि ईरान ने भी इसे लेकर अपने गुस्से का इजहार किया है। रूस ने भी तालिबानी सरकार को मान्यता नहीं दी है। इस तरह दुनिया के इस हिस्से की राजनीति कहीं न कहीं 1996 वाली राजनीति की ओर बढ़ती दिख रही है जो अफगानिस्तान को अस्थिरता और गृहयुद्ध की ओर ले जा सकती है।

1996 में जब तालिबान आया था तो पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई ने उसे मान्यता दी थी। अभी सऊदी अरब पूरी तरह खामोश है। यूएई ने थोड़ी–बहुत हरकत की है, लेकिन एक दूरी बनाकर। कतर ने तालिबान से कुछ सौदेबाजी शुरू की है, तो तुर्की उसके सपोर्ट में खड़ा है। पहले जो पश्चिम एशिया था, जिसमें एक तरफ सऊदी अरब और बाकी खाड़ी देश थे। दूसरी ओर इस्लामिक देशों की ओर से दावेदारी के लिए तुर्की खड़ा हुआ। ईरान पहले से ही इस भूमिका में था। अब इस राजनीति को तालिबान के समर्थन और विरोध में भी देखा जा सकता है।

पिछली बार जब तालिबान आया था, तब ईरान बड़ी ताकत के रूप में दिखा था। तालिबान आज ईरान को यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि शिया–सुन्नी वाले विवाद से उसका कोई लेना–देना नहीं। इसलिए उसने सऊदी से एक दूरी बनाई है। मगर यह एक प्रॉजेक्शन है कि यह अलग तालिबान है। इस बीच, ईरान ने जिस तरह से पाकिस्तान का विरोध शुरू किया है, वह दूसरी कहानी बयां करता है।

दूसरी ओर, पाकिस्तान की भी हालत खराब है। पाकिस्तान का मिलिट्री तबका अफगानिस्तान पर कंट्रोल करने का गुमान करता रहा, मगर रेकॉर्ड में हमेशा फेल रहा। जिस तरह पिछले महीनों में पाकिस्तान में हमले हुए हैं, चीन के पाकिस्तानी बेस पर भी, तो यह चीज और बढ़ सकती है क्योंकि तालिबान खुद को किसी सीमा में नहीं देखते। उनके लिए यह विचारधारा का विस्तार है कि अगर अफगानिस्तान में ऐसा हो सकता है तो पाकिस्तान में भी हो सकता है। अब अगर तालिबान वहां कुछ समय के लिए भी सरकार चला पाता है तो यह पाकिस्तान के लिए सांस लेने का मौका होगा। इसीलिए तालिबान 2.0 लोगों को यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हम बदल गए हैं। पाकिस्तान मिलिट्री भी समझ रही है कि अगर अफगानिस्तान में गृह युद्ध होता है तो उसकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी क्योंकि चीजें इस स्टेज पर हैं, जहां पर वह उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगी।

हिंदुस्तान में देखें तो यही समस्या यहां की भी बन जाती है कि आइसिस के सीरिया या खुरासान से जो वापस आने वाले गिने–चुने आतंकवादी थे, अब उनकी संख्या बढ़ सकती है। हालांकि 1996 की तुलना में भारत कश्मीर में अच्छी पोजिशन में है। पिछली बार जब तालिबान आए थे, तब कश्मीर जल रहा था। उस वक्त पाकिस्तान ने भी आग में घी डालने का काम किया। अगर इस बार भी पाकिस्तान आतंकवादियों को कश्मीर भेजता है तो समस्या बढ़ सकती है। इसलिए वहां की स्थिरता भारत के लिए भी जरूरी है।

सूडोकु नवताल- 5346

*****

7							4	
		5		3			7	
					8			2
					1	9		
	2						8	
		6	7					
1			4					
	9			2		5		
	8							1

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5345 का हल

8	4	5	6	1	3	7	2	9
7	2	6	4	9	5	3	8	1
9	3	1	7	8	2	6	5	4
1	7	2	9	6	8	4	3	5
5	6	9	3	2	4	1	7	8
4	8	3	5	7	1	9	6	2
2	9	7	1	5	6	8	4	3
3	1	8	2	4	7	5	9	6
6	5	4	8	3	9	2	1	7

अपना ब्लॉग

ऊंट किस करवट बैठता है

मोहन। मगर अफगानिस्तान का ढांचा ऐसा है जिसमें यह कहना मुश्किल होता है कि वहां एक ही सरकार का राज है। काबुल में जो अमेरिकी सपोर्ट वाली सरकार थी, उसका भी पूरे अफगानिस्तान पर नियंत्रण नहीं था। तालिबान आज कुछ इलाकों में सीधे कंट्रोल करते हैं तो कुछ में ट्राइबल लीडरशिप के जरिए कंट्रोल करते हैं। फिलहाल तो ज्यादातर कंट्रोल तालिबान के पास है। सवाल है कि यह कंट्रोल कब तक बना रहेगा और तालिबान अपने फाइटर्स और मुल्ला–मौलवियों को कंट्रोल करने में सफल नहीं होते हैं तो नतीजे क्या होंगे? फिर तालिबान ने अपने फाइटर्स को तो एक विचारधारा के तहत बरगलाया है। समाज, औरत और राजनीतिक विरोधियों के साथ उनकी अप्रोच वही पुरानी ही है। काबुल में महिलाओं के प्रदर्शन के दौरान तालिबान की हरकत सबने देखी। वे अल्पसंख्यकों, कलाकारों को टारगेट कर रहे हैं। यह सिलसिला चलता रहा तो जिन क्षेत्रों पर तालिबान का कंट्रोल है, वहां अल्पसंख्यकों का विरोध शुरू हो जाएगा और कहीं न कहीं सिविल वॉर की पोजिशन आ जाएगी। इसलिए अगले एक–डेढ़ महीने यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है।